नवभारत
संस्थापक : स्व. रामगोपाल माहेश्वरी
प्रेरणा स्रोत : स्व. प्रफुल्ल माहेश्वरी

बंजर से उपजाऊ

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम सम्मेलन में बताया कि भारत अगले 11 सालों में 2030 तक 2 करोड़ 6 लाख एकड़ बंजर भूमि को उपजाऊ भूमि बना देगा. भारत में अधिकांश मरुस्थलीय भूमि राजस्थान में है. इसका दायरा सीमित है. इसके अलावा अन्य भागों में भी काफी भूमि कई प्राकृतिक व कृत्रिम कारणों से बंजर पड़ी हुई है. जिस पर खेती नहीं हो सकती है.

कृत्रिम रूप से बंजर जमीन जंगलों की कटाई के कारण हो रही है. घने जंगलों के अंदर जाकर पेड़ों को काट दिया गया है जो नजर से ओझल रहता है. कई इलाके पथरीले हैं- लेकिन दूसरे रूप में उपयोगी है. इन्हें पत्थरों की खुली खदान कहा जाता है. देश के विकास में पत्थर का काफी बड़ा योगदान रहता है. गिट्टी और बजरी के अनेकों लाभदायी प्रयोग होते है. राजस्थान के भौगोलिक मरुस्थल को उपजाऊ नहीं बनाया जा सकता. लेकिन वहां से रेल व सड़क मार्ग से रेत का परिवहन भारत के अन्य भागों तक करके नदियों से रेत निकालने को खत्म किया जा सकता है. जो नदियों को खासकर मध्यप्रदेश में बहुत नुकसान पहुंचा रहा है. मरुस्थलों में रेत खुले में रहती है- यहां खदान की तरह या नदियों की रेत की तरह इसकी खुदाई नहीं करनी होगी. वह विशाल मात्रा में खुले में रहती है. केवल उसकी ढुलाई का खर्चा आयेगा. समुद्र तटों से खासकर गुजरात व तमिलनाडु से जहां देश का अधिकांश नमक बनाया जाता है और उसे भारत के सभी भागों में पहुंचाया जाता है. इसी तरह रेत भी प्राकृतिक मरुस्थल से सप्लाई की जा सकती है. रेत का अवैध व्यापार, चोरी और नदियों के विनाश को रोकने के लिये मरुस्थल में बेकार पड़ी रेत को व्यापारिक महत्व की बनाया जा सकता है.

जंगल कटाई रोकने व वनीकरण को गति देकर न सिर्फ जलवायु को पुन: स्वस्थ बनाया जा सकता है बल्कि इससे मरुस्थलों को भी आगे बढ़ने से रोका जा सकता है और जहां भूमि बन्जर हो गई है उसे उपजाऊ बनाया जा सकता है.

इस संदर्भ में 'बंजर भूमि' और 'मरुस्थल की भूमि' दोनों एक-दूसरे से बिल्कुल अलग है. बंजर भूमि मरुस्थल नहीं है. संसार में फैले भौगोलिक व प्राकृतिक मरुस्थल संसार में सबसे ज्यादा अरब राष्ट्रों में है और वहां भी इन्हीं मरुस्थलों में ही दुनिया का काला सोना पेट्रो क्रूड पाया जाता है. जिसने दुनिया को गति दी है और वह जीवन और विकास की नितान्त आवश्यक वस्तु बन चुका है. अरब राष्ट्रों के मरुस्थल रेत के रूप में ही वरदान है. इन्हें पेट्रो क्रूड के खेत और उसकी उपज कहा जाना चाहिए. राजस्थान, गुजरात के मरुस्थलों में पेट्रो क्रूड की खोज की जानी चाहिए. कहा जाता है कि प्रकृति की कोई चीज निरर्थक नहीं है. संसार की सारी वनस्पति औषधि व रसायन है.

इस संदर्भ में आस्ट्रेलिया एक विलक्षण राष्ट्र है. इसका 80 प्रतिशत भाग बंजर भूमि है. बीस प्रतिशत भाग जो चारों तरफ समुद्र तटों पर है वही उपजाऊ है. आस्ट्रेलिया के सभी नगर इसी 20 प्रतिशत भूमि पर समुद्र तटों पर बसे है. इसके बावजूद भी आस्ट्रेलिया इतनी कम जमीन पर इतना ज्यादा गेहूं पैदा करता है कि वह व्यापार और उसकी अर्थव्यवस्था का आधार है. भारत जैसा कृषि प्रधान देश जहां सबसे ज्यादा कृषि की उपजाऊ भूमि है, उसने आजादी के बाद कई वर्षों तक खाद्यान्न के अभाव में आस्ट्रेलिया से गेहूं लिया है. भारत में आज भी आटा मिलें आस्ट्रेलिया से गेहूं आयात करती है क्योंकि उन्हें अपने घर भारत के गेहूं से आस्ट्रेलिया का गेहूं सस्ता पड़ता है.

कृषि प्रधान भारत कृषि के क्षेत्र में अभी भी काफी पिछड़ा हुआ है. किसान की आय दुगनी करने की सरकार की नीति और लक्ष्य है तो कृषि को आधुनिक रूप से विकसित करना होगा बल्कि उसका व्यापार भी सुधारना होगा. यह भी विडम्बना है कि जब गेहूं या अन्य अनाजों के साथ सब्जियों में आलू-प्याज-लहसुन की बम्पर फसलें आती हैं तो उनके भाव क्रेश हो जाते हैं और किसान को सरकार समर्थन या राहत खरीदी से सहारा देना होता है. आस्ट्रेलिया, अमेरिका और कनाडा में गेहूं, दालों का निर्यात उनका विश्व मंडी में विकसित व्यापार है. भारत में बम्पर फसलें किसान और सरकार दोनों की मुसीबत बन जाती है.

ऐसी स्थिति व परिस्थिति में खेती को कैसे लाभ का धंधा और किसानों की आमदनी दुगनी की जा सकती है?

खुद को बचाने विपक्षी नेताओं की मशक्कत

पिछले कुछ दिनों के दौरान एक ओर देश की अर्थव्यवस्था को लेकर शंकाएं होने लगी हैं, तो दूसरी ओर सरकारी शिकंजे में फंसते जा रहे प्रमुख कांग्रेसी चेहरों के विषय अखबारों की सुर्खियां बनी हुई हैं. समूचे देश के लिए जीडीपी बढ़ने की रफ्तार का धीमा पड़ना बड़ा विषय है, जबकि नेताओं के लिए यह दोनों लगभग एक समान हैसियत रखते हैं.इसका बड़ा कारण यह है कि आम जनता को तो चुनाव के दिनों में भले ही राजनीति से वास्ता रहता हो, लेकिन बाकी दिनों में उसे अपने पेट और अपरने रोजाना के संघर्ष की चिंता अधिक होती है. नेताओं के लिए राजनीति ही उनके जीवन का अधिकांश हिस्सा होती है और अर्थव्यवस्था उसका एक हथियार है. यदि आर्थिक प्रगति की रफ्तार अच्छी होगी तो नेताओं को बिना उंगली टेढ़ी किए भी चंदा (मामा वाला नहीं) अधिक मिल जाएगा. उस समय शायद जनता की अपेक्षाएं उनसे कुछ कम रहती हैं. लेकिन जैसे ही आमदनी कमजोर हो रही होगी, तो फिर नेताओं से उम्मीदें बढ़ने लग जाती हैं. सत्ता पक्ष के लिए जीडीपी का मजबूत होना उतना ही महत्वपूर्ण है, जितना विरोधी दलों के नेताओं और खासकर प्रमुख विपक्षी पार्टी कांग्रेस के बड़े नेताओं का दागदार होते चला जाना. इसका कारण यह है कि यदि अर्थव्यवस्था कमजोर होती है और समाज में बेरोजगारी बढ़ने के साथ-साथ बेचैनी का स्तर बढ़ता है, तो बाकी मामलों में अच्छा प्रशासन होने पर भी किसी भी चुनाव में सत्ता से हटाए जाने का खतरा होता है. दूसरी ओर, यदि आर्थिक प्रबंधन बहुत अच्छा न हो, बीच का हो और तब विपक्ष के नेतागण दागदार होते चले जाएं, तो फिर चुनाव एकतरफा हो जाता है. दूसरी ओर यदि विपक्ष के नेताओं के सामने अपनी राजनीति चमकाए रखने का संकट ना हो तो उनसे बड़ा खुश कौन होगा? बिल्ली के भाग्य से छींका हमेशा नहीं टूटता, लेकिन कई बार चमत्कार हो जाता है और बैठे-बिठाए 5 साल के बाद सत्ता परिवर्तन का सुख पाले से बाहर बैठे लोगों के हिस्से में अपने आप चला जाता है.

- विपक्ष के नेताओं ने पिछले 5 वर्षों के दौरान अपने ऊपर सरकारी शिकंजा कसा जाता हुआ महसूस किया है और उसकी तार्किक परिणति अब जाकर हो रही है. शायद इसीलिए सबने पिछले आम चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जमकर प्रचार किया था. लेकिन उनका दांव बेकार गया और अब उन्हें अपनी राजनीति नहीं, बल्कि खुद को बचाने की मशक्कत करनी पड़ रही है.
- यह किसे मालूम था कि सरकार के पहले 100 दिन के एजेंडा में पी. चिदम्बरम को तिहाड़ जेल पहुंचाना भी शामिल था. भारतीय राजनीति में यह एक बहुत बड़ी घटना है और इसकी गूंज आगामी कई दशकों तक सुनी जाती रहेगी. वैसे सीबीआई द्वारा चिदंबरम की गिरफ्तारी किये जाने से भी राजनीतिक रूप से अधिक महत्वपूर्ण कर्नाटक के पूर्व मंत्री डीके शिवकुमार की ईडजी द्वारा गिरफ्तारी है.
- इसका बड़ा कारण यह है कि चिदंबरम का सारा मामला उनके अपने परिवार तक सीमित है और उसका कोई राजनीतिक विस्तार नहीं होगा. लेकिन शिवकुमार के मामले में ऐसा नहीं कहा जा सकता. वह तो एक बीज हैं और आगे यह वटवृक्ष कितना बड़ा बनने वाला है, यह कौन कह सकता है? इसलिए चिदम्बरम को तो अपनी अदालती लड़ाई भर लड़नी है लेकिन शिव कुमार का मामला हनुमान जी की पूंछ की तरह लगातार लंबा होता चला जाएगा.

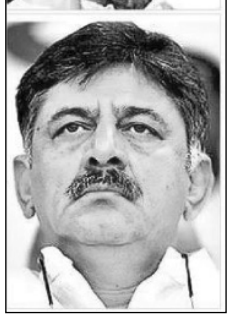

भाजपा गमन के 4 कारण

विभिन्न दलों से निकलकर भाजपा में जाने वालों की जो लाइन लगी हुई है, उसके 4 प्रमुख कारण एक चर्चित कांग्रेसी नेता ने निजी चर्चा में बोले. पहला, वे लोग जा रहे हैं, जो विभिन्न तरह के घोटाले में फंसे हुए हैं. दूसरा, जिनके व्यावसायिक प्रतिष्ठान या सहकारी उद्योग कर्ज से लेकर अन्य झंझटों में हैं. तीसरे वैसे हैं, जो बीजेपी नेताओं के थोड़े से चमकाने पर ही घबरा जा रहे हैं. इनके अलावा कई ऐसे हैं, जिनको अपनी पार्टी में विभिन्न कारणों से घुटन हो रही है. महाराष्ट्र में तो झड़ी लगी हुई है. इस सबके बावजूद कांग्रेस के एक युवा नेता ने राज्य के प्रमुख भाजपा नेताओं से इतना कहने का साहस तो किया ही है कि सत्ता आनी और जानी है, लेकिन इस चक्कर में राज्य की अब तक की राजनीतिक संस्कृति व परंपरा को खराब ना करें. प्रदेश में हमेशा से यह माहौल रहा है कि निजी मसलों के साथ-साथ राज्य के हितों के मामले पर सभी दलों के नेता एक साथ आ जाते हैं और एक-दूसरे से मिलते समय उन्हें नजर चुराने की जरूरत नहीं पड़ती है. परंतु कांग्रेस और एनसीपी के कई नेता ऐसा मान रहे हैं कि सत्ता में होने का लाभ उठाते हुए भाजपा और शिवसेना जिस तरह से दूसरे दलों पर हर तरह के हथकंडे का प्रयोग करते हुए तोड़फोड़ करने में जुटे हुए हैं. वह इस पुरानी साख को काफी चोट पहुंचा चुकी है. शायद इसके बाद जब कभी भी सत्ता परिवर्तन होगा, तो रिवर्स गियर जरूर लगेगा और सरकारी एजेंसियों की दबिश भाजपा नेताओं और उनसे जुड़े संस्थानों को भी झेलनी पड़ जाएगी.

- अनुज गुप्त

मां और शिशु तक नहीं पहुंच पा रही है पोषक खुराक

> भारत में पूरक पोषण कार्यक्रम के तहत गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महज 46 फीसदी महिलाओं को ही राशन मिल पाता है. नीति आयोग की ओर से कराए गए एक सर्वेक्षण में यह बात सामने आई है. इस कार्यक्रम के तहत पंजीकरण कराने वाली महिलाओं की दर 78 फीसदी है. इस सर्वेक्षण से यह भी पता चला है कि आंगनबाड़ी योजना में पंजीकृत 64 फीसदी बच्चों में से सिर्फ 17 फीसदी को ही दिन में एक बार गर्म भोजन मिल पाता है. इससे पहले एक अन्य सर्वेक्षण में कहा गया था भारत में हर तीसरी महिला कुपोषित है जबकि हर दूसरी महिला में खून की कमी है.

ऐसी महिलाओं के बच्चों का वजन जन्म के समय काफी कम होता है. यह स्थिति तब है जब देश में हर साल सितंबर के पहले सप्ताह के दौरान राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया जाता है. इस साल तो पूरे सितंबर के दौरान राष्ट्रीय पोषण माह का पालन किया जा रहा है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2022 तक कुपोषण खत्म करने की बात कही है. केंद्रीय महिला व बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने भी इसी नीति के तहत वर्ष 2022 तक कुपोषण मुक्त भारत का लक्ष्य हासिल करने का नारा दिया है लेकिन भारत में कुपोषण की समस्या इतनी व्यापक व जटिल है कि इससे निपटना आसान नहीं है.

ताजा सर्वेक्षण: नीति आयोग की ओर से 27 जिलों में कराए गए सर्वेक्षण के मुताबिक 78 फीसदी पंजीकरण कर के बावजूद गर्भवती और स्तनपान कराने वाली केवल 46 फीसदी महिलाओं को पूरक पोषण कार्यक्रम के अंतर्गत टेक होम यानी घ्र लेजाने के लिए राशन मुहैया कराया गया. इसके साथ ही आंगनबाड़ी में पंजीकृत 64 फीसदी बच्चों में से सिर्फ 17 फीसदी बच्चों को ही दिन में गर्म खाना मिला. इस स्थिति से निपटने के लिए नीति आयोग ने स्वास्थ्य मंत्रालय की देखरेख में समुदाय आधारित कुपोषण प्रबंधन (सीएमएएम) और विभिन्न राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में आंगनबाड़ी सेवा के खाली पदों को शीघ्र भरने की सिफारिश की है. सीएमएएम व्यवस्था के तहत कुपोषित बच्चों का उनके पोषण और चिकित्सकीय जरूरतों के अनुरूप इलाज किया जाता है. आयोग में सलाहकार आलोक कुमार कहते हैं, अपनी सर्वेक्षण रिपोर्ट के आधार पर हमने कई सिफारिशें की हैं. उन पर अमर के जरिए इन खआमियों को दूर किया जा सकता है. इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज के पूरक पोषण कार्यक्रम के तहत छह महीने से छह साल तक के बच्चों और गर्भवती व स्तनपान कराने वाली महिलाओं को पूरक पोषण दिया जाता है.

क्या कहते हैं आंकड़े: स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार देश में पांच साल से कम उम्र के 50 फीसदी बच्चे और 30 फीसदी गर्भवती महिलाएं कुपोषण की शिकार हैं. इसमें ज्यादातर ऐसे गरीब परिवार शामिल हैं जो अपने भोजन में पौष्टिक चीजों को शामिल नहीं कर पाते. भारत में 1.08 लाख शिशु एक महीने और 17 लाख बच्चे एक साल की उम्र पूरा करने से पहले मौत के शिकार

जरूरतमंदों तक कैसे पहुंचे योजनाओं का लाभ

भारत को कुपोषण मुक्त करने के प्रयासों के तहत सरकार ने राष्ट्रीय पोषण मिशन का नाम बदलकर पोषण अभियान कर दिया है. नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि देश में हर तीसरा बच्चा कुपोषित है. कुपोषण की शुरुआत बच्चे से नहीं बल्कि गर्भवती माता से होती है. इस मामले में सबसे ज्यादा खराब स्थिति महिलाओं की है. स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि कुपोषण का एक बड़ा कारण आर्थिक रूप से कमजोर व पिछड़े वर्ग की महिलाओं का प्रसव से पहले तक मजदूरी पर जाते रहना और प्रसव के चंद दिनों बाद ही फिर काम पर लौट जाना है. एक पोषणविद् कहती हैं, पेट की आग बुझाने के लिए काम पर जाने की वजह से महिलाएं गर्भकाल के दौरान और प्रसव के बाद भी अपना व नवजात शिशु के स्वास्थ्य पर समुचित ध्यान नहीं दे पाती है.

पत्र email करें: nbp_bhopal@rediffmail.com

विज्ञान की दुनिया

वैज्ञानिकों ने खोजे सोने से बने ग्रह

वैज्ञानिकों ने दो न्यूट्रान स्टार के बीच टकराव का अवलोकन करने के दो वर्ष बाद अब पता किया है कि इससे भारी मात्रा में सोना और प्लेटिनम पैदा हो गया है. वैज्ञानिकों के अनुसार, उन्होंने 2017 में जो टकराव देखा था, उससे वे 2016 में हुई इसी तरह की घटना पर दोबारा नजर डालने को मजबूर हो गए. तब उन्हें पता चला कि उस घटना में दो न्यूट्रान स्टार ने आपस में विलय कर किलोनोवा पैदा किया. बड़े-बड़े तारों के विस्फोट और टूटने के बाद बचे अवशेष न्यूट्रॉन स्टार कहे जाते हैं. न्यूट्रॉन स्टार जब ब्लैक होल में मिल जाते हैं तो भी किलोनोवा का निर्माण होता है. 2016 में हुआ टकराव और फिर 2017 में उसी तरह की घटना से भारी मात्रा में सोना और प्लैटिनम पैदा हुआ. वैज्ञानिकों का मत है कि अब वे पृथ्वी पर सोने और प्लैटिनम की मौजूदगी की व्याख्या कर पाएंगे. उन्हें लगता है कि ये बहुमूल्य धातु लाखों वर्ष पहले बने किलोनोवा के निर्माण के ही परिणाम हैं. सोने का यह भंडार गैलेक्सी एनजीसी 4994 में पाया जा सकता है जो पृथ्वी से 130 से 140 प्रकाश वर्ष दूर है. यानी, न्यूट्रॉन स्टार के बीच आज से 13 से 14 करोड़ वर्ष पहले टकराव हुआ था. यह अलग बात है कि इस पर वैज्ञानिकों की नजर कुछ साल पहले पड़ी. कुछ अंदाजा लगा पाएंगे कि पृथ्वी कर पाए जाने वाले गोल्ड के मुकाबले गैलेक्सी एनजीसी 4994 में कितना सोना है? दावा है कि पृथ्वी पर खानों से अब तक निकाले गये सोने को 20 मीटर के (क्यूब) घन में काटकर रखा जा सकता है.

अजब-गजब

सबसे ज्यादा जीते हैं कश्मीरी

कश्मीर के एक वर्ष के बच्चे की जीवन प्रत्याशा भारत के किसी भी दूसरे राज्य से ज्यादा है. इसी तरह केवल बिहार और झारखंड ही ऐसे राज्य हैं, जहां पुरुषों की जीवन प्रत्याशा या औसत जीवनकाल महिलाओं से ज्यादा है, जबकि केरल एकमात्र ऐसा राज्य है, जहां ग्रामीणों की औसत आयु शहर में रहने वालों से ज्यादा है. ये आंकड़े हाल ही में महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त के कार्यालय ने जारी किए हैं. भारत में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा 49.7 वर्ष (1970-75) से 19.3 वर्ष बढ़कर 69 वर्ष (2013-17) हुई है. भारतीयों के औसत जीवनकाल में यह बढ़ोतरी पिछले 40 वर्षों में हुई है.

हालांकि 50 वर्ष पहले जन्म के समय पुरुषों की जीवन प्रत्याशा महिलाओं से ज्यादा थी लेकिन 1981-85 के बीच यह ट्रेंड उलट गया और अब भारत में भी दुनिया भर की तरह महिलाओं की जीवन प्रत्याशा पुरुषों से ज्यादा हो गई है. 2013-17 में पुरुषों के 67.8 वर्ष की तुलना में महिलाओं की जीवन प्रत्याशा 70.4 वर्ष हुई है. वैसे तो भारत में जीवन प्रत्याशा में बढ़ोतरी हुई है. लेकिन अभी भी वह अपने पड़ोसियों-बांग्लादेश (2017 में 72.8), नेपाल (70.6), श्रीलंका (75.5) और चीन (76.4), से पीछे है. संतोष की बात इतनी है कि पाकिस्तान (66.6) हमसे पीछे है.

संपादकीय बोर्ड प्रबंध संपादक : सुमीत माहेश्वरी, समूह संपादक : क्रांति चतुर्वेदी

पत्र संपादक के नाम

सकारात्मक चश्मे से देखें

पिछले दिनों एक खबर आई और गई लेकिन उस पर बहुत कम ध्यान दिया गया. खबर के नकारात्मक पक्ष पर तो ध्यान दिया गया लेकिन उसकी सकारात्मकता सुर्खियां नहीं बन पाई. खंडवा जिले के प्राथमिक स्कूल सिहाड़ा में बच्चों से टॉयलेट साफ कराने पर जो वीडियो वायरल हुआ था उस पर विवाद खड़ा हो गया. लेकिन इस विवाद का सबसे सकारात्मक पक्ष यह रहा कि कलेक्टर ने कहा कि सारे बच्चे टॉयलेट क्या स्कूल साफ करें तो गलत क्या है. उन्होंने जापान से तुलना करते हुए कहा कि जापान के सारे बच्चे स्कूल के हर काम में लगे रहते हैं तो उनको लगता है कि यह स्कूल मेरा है इसे गंदा नहीं कर सकता.

आज स्कूलों में बच्चों से साफ सफाई करवाने पर फोटो व समाचार छप जाते हैं व अनावश्यक तनाव पैदा कर दिया जाता है. जबकि हमारे देश की गुरुकुल परंपरा में चाहे भगवान राम हो या कृष्ण, राजा हो या महाराजा सभी ने अपनी शिक्षा के समय चाहे आश्रम की साफ-सफाई, पानी लाना, लकड़ी लाना या अन्य काम करते थे क्योंकि यह शिक्षा जीवनोपयोगी है. काम करने से बच्चों का शारीरिक विकास भी होता है. जब देश में स्वच्छ भारत अभियान चलाया गया तो प्रधानमंत्री जी ने देश के प्रत्येक व्यक्ति को सफाई के प्रति जागरूकता का संदेश दिया था. तो स्कूलों में साफ सफाई करने पर कोई बुराई नहीं है.

हरि उपाध्याय
खाचरोद

पत्र विशेष

कांग्रेस में सत्ता व पद की लड़ाई

मप्र कांग्रेस में इन दिनों सत्ता व संगठन में विरोध का जो दौर चल रहा है वह कांग्रेस की सेहत के लिए ठीक नहीं दिख रहा है. दिग्विजय सिंह, अरुण यादव, उमंग सिंघार के बीच जो बयानबाजी हो रही है वह कांग्रेस के अंतर्कलह को सार्वजनिक कर रही है. कांग्रेस में जो घमासान चल रहा है उसे देख कर लग रहा है कि हर कोई सत्ता व पद के लिए तड़प रहा है. अनुशासन को ताक में रख दिया गया. भाजपा में जरा-सी भी कोई खटपट होती थी तो कांग्रेसी तिल का पहाड़ बना देते थे. अब खुद अपने घर में जो कलह हो रहा उस पर कोई कुछ नहीं बोल रहा? कांग्रेसी अब कम से कम इस सच्चाई को स्वीकार करे कि भाजपा अनुशासन के मामले में कांग्रेस से काफी आगे है. **शिरीष सकलेचा, बड़ावदा**

पत्र email करें: nbp_bhopal@rediffmail.com

अमृत वचन

कर्मयोग

निष्काम कर्म ही कर्मयोग है. सभी लोगों को अपने कर्म पूरी तन्मयता से और बगैर किसी प्रकार के लाभ की भावना से करना चाहिए. माली को जी-जान से सर्वोत्तम बाग विकसित करने का प्रयास करना चाहिए, शिक्षक को अपने छात्रों को पूरी तन्मयता से पढ़ाने का प्रयास करना चाहिए और एक चिकित्सक को अपने रोगी को ठीक करने का प्रयास करना चाहिए. पर यह सब करना चाहिए स्वयं को ईश्वर का उपकरण मात्र मानकर. हमें तो बस, बागरूपी ईश्वर की, छात्ररूपी ईश्वर की, रोगीरूपी ईश्वर की सेवा-सहायता भर करनी है. इसमें मान-सम्मान, यश-धन पाने की लालस ही न हो. ये सब पाने की लालस न होने पर हम मान-सम्मान, यश-धन से वंचित हो जाएंगे ऐसा नहीं है. हमें मिलेगा सब कुछ, पर हम उनके फलों से बंधेंगे नहीं, क्योंकि उनके प्रति हमारी आसक्ति ही नहीं रहेगी.

निशानेबाज

जुर्माने की रकम से लोगों में खौफ

अगर यही रहे हालात तो सभी अपने वाहन बेच देंगे

पड़ोसी ने हमसे कहा, ''निशानेबाज, संशोधित मोटर वाहन कानून लागू होने के बाद से लोगों में जुर्माने की भारी-भरकम राशि को लेकर खौफ है. अब तो गाड़ी सड़क पर निकालने में भी डर लगता है.''

हमने कहा, ''आप ट्रैफिक नियमों का सावधानी से पालन कीजिए. सारे जरूरी डाक्यूमेंट साथ रखिए तो डर कैसा! आपके पास वैध लाइसेंस, आरसी बुक या कार्ड, गाड़ी का इंश्योरेंस, पल्यूशन कंट्रोल सर्टिफिकेट रहना चाहिए. गाड़ी जेबरा लाइन के पीछे रखें. सिग्नल कभी न तोड़ें. स्पीड लिमिट का ध्यान रखें. नशे की हालत में गाड़ी न चलाएं, वाहन चलाते समय मोबाइल पर बात न करें. टूव्हीलर चलाते समय हेलमेट जरूर पहनें. गाड़ी सावधानी से चलाएं ताकि अपनी व किसी दूसरे की जान को खतरा न होने पाए. सिर्फ इतनी सी बात के लिए क्यों परेशान हैं?''

पड़ोसी ने कहा, ''निशानेबाज, हमें तो नींद में गाड़ी चालान होने के डरावने सपने आ रहे हैं. इससे मन में बेचैनी बनी रहती है. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ओडिशा के संबलपुर जिले में अब तक का सबसे बड़ा चालान कटा है. वहां जेसीबी मशीन ट्रक पर ले जा रहे व्यक्ति पर 86,500 रुपए जुर्माना लगा. भुवनेश्वर में एक आटोरिक्शा वाले पर 47,500 रुपए जुर्माना हुआ. उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन प्रमाणपत्र और इंश्योरेंस सर्टिफिकेट कुछ भी नहीं था. उसने शराब भी पी रखी थी. ऐसी खबरें पढ़कर हमारा दिल डूबा जा रहा है. ट्रैफिक पुलिस को देखते ही हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं. कलेजा मुंह को आ जाता है.''

हमने कहा, ''आप आजाद देश के आजाद नागरिक हैं. निर्भय रहिए. जुर्माने की राशि बढ़ाने से सरकार को 2 फायदे होंगे. एक तो लोग डर की वजह से यातायात कानून का पालन करेंगे, इससे दुर्घटनाओं में कमी आएगी. दूसरा फायदा यह कि सरकार की आय बढ़ेगी जिससे वह विकास कार्य करेगी.''

पड़ोसी ने कहा, ''निशानेबाज, सड़कों पर चंद्रमा के धरातल के समान गड्ढे हैं. हाल ही में बने सीमेंट रोड में दरार आ गई है. सड़कें पानी में डूब जाती हैं. इन दिक्कतों से नागरिक जैसे-तैसे जूझ रहे हैं, ऊपर से जुर्माने की राशि भी मनमानी बढ़ा दी गई. सरकार ने जनता को गरीब की गाय समझ रखा है. अगर यही हालात रहे तो सभी अपने वाहन बेच देंगे.''